आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
गुरुवार 24.09.2026
समय 07.20

मुख्य समाचार :

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 306 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति दी।
- मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रदेश की प्रमुख पेयजल योजनाओं की 15 दिन में जियो मैपिंग और भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए।
- ऋषिकेश के शिवपुरी में रिवर राफ्टिंग सीजन 2026–27 शुरू।
- कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राज्य की किसान कल्याण योजनाओं में तेजी लाने और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

वित्तीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सड़क अवसंरचना, पर्यटन विकास, बाढ़ सुरक्षा सहित विभिन्न विकास कार्यों के लिए 306 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृतियां दी हैं। इनमें केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के तहत नौ कार्य भी शामिल हैं। इन कार्यों के लिए पहली किश्त के रूप में 115 करोड़ 36 लाख रुपये जारी किए जाएंगे।

बद्रीनाथ धाम में रिवर फ्रंट विकास कार्य की संशोधित लागत को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में पर्यटन अवस्थापना मद से धनराशि स्वीकृत की जाएगी।

मानसून अवधि में बाढ़ सुरक्षा, क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और अन्य बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के लिए पिथौरागढ़, चमोली, देहरादून, उत्तरकाशी और पौड़ी गढ़वाल की छह योजनाओं को स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा अल्मोड़ा के सल्ट में शक्तिपीठ भौनादेवी मंदिर और जागेश्वर के चलनीछीना में घटीका मंदिर के सौंदर्यीकरण को भी मंजूरी मिली है।

बैठक / निर्देश–1

नैनीताल के ज्योलिकोट में दूषित पेयजल की घटना को लेकर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने मामले में संबंधित अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई और पेयजल की गुणवत्ता तथा जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट–

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में व्यापक फील्ड नेटवर्क होने के बावजूद घटना की जानकारी समय पर नहीं मिल सकी। उन्होंने शिक्षक, पटवारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और ट्यूबवेल ऑपरेटर सहित फील्ड कर्मचारियों के नेटवर्क का प्रभावी उपयोग करते हुए सूचना और फीडबैक व्यवस्था मजबूत करने को कहा।

श्री बर्द्धन ने प्रदेश की प्रमुख पेयजल योजनाओं की जियो मैपिंग और भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए। अगले 15 दिनों में इन योजनाओं के स्रोत, स्टोरेज, पाइपलाइन, सीवर लाइन और क्रॉसिंग प्वाइंट्स की जांच की जाएगी। संभावित लीकेज के साथ स्टोरेज टैंकों की सफाई, क्लोरीनेशन और पानी की गुणवत्ता से जुड़े जरूरी मानकों की भी जांच की जाएगी।

मुख्य सचिव ने पेयजल और सीवरेज लाइनों की जांच के लिए स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिय– एसओपी तैयार कर उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने प्रमुख पेयजल परियोजनाओं की नियमित निगरानी के निर्देश भी दिए।

आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से हिना

बैठक / निर्देश–2

इस बीच, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रमुख शहरों में नियमित पेयजल गुणवत्ता जांच कराने और सभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का अचानक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग को दूषित पेयजल की सूचना मिलने पर तत्काल स्वास्थ्य टीम भेजने और अगले 15 दिनों में प्रदेशभर में आवश्यक स्वास्थ्य निगरानी एवं जांच सुनिश्चित करने को कहा गया है।

मुख्य सचिव ने जिला स्तर पर सूचना और फीडबैक के लिए स्थायी निगरानी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटना होने पर प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर विभागाध्यक्षों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में जिम्मेदारी तय की जाएगी।

समझौता

प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग और एम–थ्री–एम फाउंडेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। देहरादून में हुए इस समझौते का उद्देश्य युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण देकर उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाना है।

समझौते के तहत शुरुआती चरण में देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर और पिथौरागढ़ में प्रशिक्षण केंद्रों को प्राथमिकता दी गई है। जरूरत और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर अल्मोड़ा और बड़कोट को भी अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्र के रूप में शामिल किया जा सकता है।

प्रशिक्षण केंद्रों पर स्थानीय उद्योगों की मांग और रोजगार की संभावनाओं के अनुसार कम से कम दो पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इनमें इलेक्ट्रिक वाहन तकनीशियन, ऑटो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, ऑटोमोबाइल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी और प्लंबिंग से जुड़े पाठ्यक्रम शामिल हैं।

इस साझेदारी के तहत युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण के साथ रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। उद्योगों के साथ संपर्क और प्रशिक्षण के बाद रोजगार दिलाने की व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा।

रिवर राफ्टिंग सीजन 2026–27 शुरू

ऋषिकेश के शिवपुरी में रिवर राफ्टिंग सीजन 2026–27 की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से आयोजित समारोह में कल प्रदेश की पंजीकृत राफ्टिंग फर्मों को राफ्टिंग लाइसेंस वितरित किए गए। लाइसेंस मिलने के बाद गंगा, काली, टौंस, गोरी, कोसी, अलकनंदा, पिंडर, सरयू, रामगंगा, भागीरथी और धौलीगंगा सहित विभिन्न नदियों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत राफ्टिंग गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी।

पर्यटन विभाग के अनुसार, लाइसेंस व्यवस्था का उद्देश्य राफ्टिंग को व्यवस्थित करने के साथ पर्यटकों की सुरक्षा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है।

पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि राफ्टिंग गाइडों की सुरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए हनीफ्ल सेंटर और एरी बैककंट्री मेडिसिन यानी एबीएम, अमेरिका के सहयोग से वाइल्डरनेस फर्स्ट–एड और सीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इसके तहत चरणबद्ध रूप से 700 गाइडों को प्रशिक्षित किया जाना है।

उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने प्रशिक्षित गाइडों के डिजिटल प्रमाणीकरण और पहचान के लिए टूरिस्ट गाइड पोर्टल भी विकसित किया है। अब तक 300 से अधिक रिवर राफ्टिंग गाइड इस पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। जल्द ही पर्यटकों को पोर्टल के माध्यम से गाइड से सीधे संपर्क और बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराने की योजना है। उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग और क्याकिंग नियमावली–2014 के प्रावधानों के तहत सभी पंजीकृत राफ्टिंग फर्मों को 23 सितंबर से 45 दिनों की अस्थायी अनुज्ञा दी गई है। निर्धारित प्रक्रिया और शुल्क पूरा करने के बाद फर्में स्थायी अनुज्ञा प्राप्त कर सकेंगी।

आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुन्द्रियाल

समीक्षा

कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में कृषि और उद्यान विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को किसान कल्याण योजनाओं में तेजी लाने और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। श्री जोशी ने पॉलीहाउस निर्माण, शीतकालीन फसलों के लिए बीज–पौध वितरण और बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का आकलन कर किसानों को जल्द क्षतिपूर्ति देने पर विशेष जोर दिया।

पॉलीहाउस योजना की समीक्षा के दौरान कृषि मंत्री ने राज्य में 14 हजार 777 पॉलीहाउस निर्माण के लक्ष्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने 31 अक्टूबर तक 50 प्रतिशत काम पूरा करने की समय–सीमा तय की। अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में स्वीकृत 2 हजार 700 पॉलीहाउस में से एक हजार का निर्माण शुरू हो चुका है।

गणेश जोशी ने राजमा की फसल को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को नीतिगत प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने शीतकालीन फसलों के लिए बीज और पौध वितरण तत्काल शुरू करने को भी कहा।

कृषि मंत्री ने राज्य में जैविक खेती के विस्तार, मखाना उत्पादन की संभावनाओं और चंपावत में गेहूं की खेती को बढ़ावा देने से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा की। किसानों की उपज के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज निर्माण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए।

बहुउद्देशीय शिविर

टिहरी में केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए 25 सितंबर से 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने बताया कि शिविर के पहले दिन विभिन्न विभागों के अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।

शिविरों में करीब 23 विभागों के अधिकारी ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे और पात्रता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही, लोगों की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण की कार्रवाई भी की जाएगी।

जिलाधिकारी के अनुसार, शिविरों का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने के साथ उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना है।